संपादकीय

महायुद्ध का भय और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौती

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया को संभावित महायुद्ध की आशंका के सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिका द्वारा इजरायल के सहयोग से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता और गहरी हो गई है। 28 फरवरी 2026 को शुरू की गई इस सैन्य कार्रवाई ने न केवल क्षेत्रीय शांति को प्रभावित किया है, बल्कि इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। अमेरिकी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि यह युद्ध कई सप्ताह तक चल सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। सैन्य कार्रवाई के शुरुआती चरण में ही ईरान के अनेक सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इस अभियान में अमेरिका ने अत्याधुनिक हथियारों और महंगे सैन्य उपकरणों का उपयोग किया है। बी-2 स्टील्थ बॉम्बर, एफ-35 और एफ-22 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। इतने बड़े सैन्य अभियान के कारण अमेरिका पर आर्थिक बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, केवल शुरुआती दिनों में ही अरबों डॉलर का खर्च हो चुका है और यदि युद्ध लंबा चलता है तो यह लागत कई गुना बढ़ सकती है।

युद्ध का सबसे तात्कालिक प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की आशंका ने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर धकेल दिया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यदि तनाव लंबे समय तक बना रहा तो तेल की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति होती है। इस मार्ग के बाधित होने से ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

तेल की बढ़ती कीमतों का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इससे परिवहन लागत, उत्पादन लागत और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप वैश्विक महंगाई दर में वृद्धि की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी बढ़ सकती है। इस संघर्ष का असर निवेश बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशक अस्थिर परिस्थितियों में सुरक्षित निवेश की ओर झुकते हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कई देशों के केंद्रीय बैंक भी अपने स्वर्ण भंडार बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। इससे वैश्विक बाजार में सोने की मांग और भी बढ़ रही है। यदि भू-राजनीतिक तनाव इसी तरह बना रहा तो आने वाले समय में सोने की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं।

भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव घरेलू महंगाई पर पड़ सकता है। साथ ही, पश्चिम एशिया में काम करने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। भारत सरकार ने पहले ही वहां फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कूटनीतिक संवाद और शांतिपूर्ण समाधान ही इस संकट से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी मार्ग हो सकता है। यदि संघर्ष को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी देश संयम और संवाद के माध्यम से शांति की दिशा में ठोस पहल करें, ताकि संभावित महायुद्ध की आशंका को टाला जा सके और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखा जा सके।

आजकल

सत्ता की राजनीति में चंदे का बढ़ता असंतुलन

भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चुनावी गतिविधियों, संगठन विस्तार और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। हाल ही में राष्ट्रीय दलों की आय संबंधी रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि राजनीतिक चंदे का बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल की ओर झुकता जा रहा है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की कुल आय लगभग 6769 करोड़ रुपये रही, जो अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आय घटकर लगभग 918 करोड़ रुपये रह गई। यह अंतर भारतीय राजनीति में वित्तीय असंतुलन की ओर संकेत करता है।

इस असंतुलन के पीछे कई कारण हैं। पहला, सत्ता में रहने वाले दलों के पास प्रशासनिक प्रभाव और राजनीतिक पहुंच अधिक होती है, जिसके कारण बड़े कॉरपोरेट और संस्थागत दाताओं का झुकाव उनकी ओर बढ़ जाता है। दूसरा, राजनीतिक चंदे के स्रोतों में पारदर्शिता की कमी भी इस असमानता को बढ़ाती है। लंबे समय तक लागू रही इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर भी यही आलोचना की गई कि इससे दानदाताओं की पहचान सार्वजनिक नहीं होती थी और इससे सत्ता के निकट दलों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता था।

विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी है। जब किसी दल के पास सीमित वित्तीय साधन होते हैं, तो वह चुनाव प्रचार, डिजिटल अभियान और संगठनात्मक विस्तार में सत्ताधारी दल के बराबर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता।

इससे चुनावी मैदान में बराबरी का अवसर प्रभावित होता है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक वित्तपोषण में बढ़ता यह अंतर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े करता है। यदि चंदे का बड़ा हिस्सा एक ही दल के पास केंद्रित हो जाए, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो सकती है और नीति-निर्माण पर आर्थिक हितों के प्रभाव की आशंका भी बढ़ जाती है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए राजनीतिक चंदे की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। चुनाव आयोग की निगरानी को मजबूत करना, दान की जानकारी सार्वजनिक करना और सभी दलों के लिए समान वित्तीय अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल संसाधनों की ताकत पर नहीं, बल्कि विचारों, नीतियों और जनसमर्थन के आधार पर तय हो।

सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना

किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जनऔषधि परियोजना का रणनीतिक विकास

जगत प्रकाश नड्डा

जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ

वैश्विक स्तर पर, जेनेरिक दवाइयाँ सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मूलभूत आधारशिला हैं। विश्वभर में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुल दवाइयों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 80-90% है और इसने आवश्यक दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि जेनेरिक दवाइयाँ पैकेज, लेबल और निष्क्रिय अवयव की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि ये अंतर उनके चिकित्सीय प्रभाव पर असर नहीं डालते हैं। खुराक, सुरक्षा, क्षमता, गुणवत्ता और लक्षित उपयोग के संदर्भ में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की समकक्ष हैं तथा उत्पादन और गुणवत्ता के कठोर मानकों का समान रूप से पालन करती हैं। पीएमबीजेपीकेवल एक खुदरा-बिक्री कार्यक्रम नहीं है; यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संरचनात्मक सशक्तिकरण को दर्शाता है।

किसी राष्ट्र की प्रगति का असली पैमाना अक्सर इस बात से परिलक्षित होता है कि उसके नागरिक स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक कितनी आसानी से पहुँच सकते हैं। दशकों तक, भारत के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए दवाओं की उच्च लागत एक प्रमुख वित्तीय बाधा रही है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उनके ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है।यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करके एक व्यापक और व्यवस्थित परिवर्तन लाने में सफल रही है।

वैश्विक स्तर पर, जेनेरिक दवाइयाँ सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मूलभूत आधारशिला हैं। विश्वभर में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुल दवाइयों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 80-90% है और इसने आवश्यक दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि जेनेरिक दवाइयाँ पैकेज, लेबल और निष्क्रिय अवयव की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि ये अंतर उनके चिकित्सीय प्रभाव पर असर नहीं डालते हैं। खुराक, सुरक्षा, क्षमता, गुणवत्ता और लक्षित उपयोग के संदर्भ में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की समकक्ष हैं तथा उत्पादन और गुणवत्ता के कठोर मानकों का समान रूप से पालन करती हैं। पीएमबीजेपीकेवल एक खुदरा-बिक्री कार्यक्रम नहीं है; यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संरचनात्मक सशक्तिकरण को दर्शाता है। यह इस साल के जनऔषधि सप्ताह के थीम में परिलक्षित होता है, 'जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ 'यह थीम लाखों लाभार्थियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। 18,000 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से, योजना ने सुनिश्चित किया है कि दवाइयाँ बाजार दरों की तुलना में 50% से 80%तक की कम कीमतों पर उपलब्ध हों और सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों को समर्थन प्रदान करती हों। क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चला है कि लाभार्थी लागत बचत और दवाइयों तक बेहतर पहुँच की सराहना करते हैं।

योजना का पैमाना इसके उत्पाद संग्रह से भी परिलक्षित होता है। जनऔषधि 2,110 दवाओं और 315 सर्जिकल उत्पादों का विस्तृत संग्रह पेश करता है, जो 29 विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों को शामिल करती है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के प्रत्यक्ष देखरेख में,संग्रह का विस्तार एक गतिशील, डेटा-संचालित प्रक्रिया है, जिसमें बाजार विश्लेषण, हितधारकों की भागीदारी और एक समर्पित विशेषज्ञ समिति की कठोर निगरानी शामिल हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि योजना देश की बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और औषधीय मांगों के अनुरूप विकसित होती रहे।

कठोर नियामक निरीक्षण के साथ, भारतीय दवा कंपनियां 200 से अधिक देशोंके लिए भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बन गई हैं, जिसमें अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं। भारतीय दवा कंपनियां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोपजैसे उभरते बाजारों में भी विस्तार कर रही हैं।

यह उद्योग जैविक दवाओं के समान दवाओं (बायोसिमिलर), जैविक दवाओं के जेनेरिक प्रतिरूपों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही जटिल जेनेरिक और विशेष दवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास में भी अधिक निवेश कर रहा है। ये दूरदर्शी कार्यक्रम भारत को न केवल एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में, बल्कि किफायती दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के नवाचार अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित करते हैं।

गुणवत्ता बनाम मूल्य पर बहस कभी-कभी सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है। एक बहु-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था के माध्यम से,पीएमबीजेपी ने इस मिथक को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया है कि किफायती होना निर्माण मानकों में समझौते का संकेत देता है। दवाइयाँ डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी जाती हैं, जो वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं।नियम निर्धारित करते हैं कि फार्मेसी की शेल्फ तक पहुंचने सेपहले दवा के हर बैच काराष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं में सख्त सत्यापन होना आवश्यक है। ये दवाइयाँ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940के नियमों का पालन करती हैं और ब्रांडेड विकल्पों के सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों के अनुरूप हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद से पहले सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और खरीद के बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, पीएमबीआई नियमित रूप से दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और समीक्षा करती है, ताकि स्थापित विनियमों के पालन में कोई कोताही न होना सुनिश्चित किया जा सके।

एक आईटी-संचालित वितरण नेटवर्क, जिसे पांच अत्याधुनिक भंडार गृहों और देशभर के में 41 विशेष वितरकों का समर्थन प्राप्त है,ने सुनिश्चित किया है कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ सुदृढ़ बनी रहे।

तीन स्तंभों -पहुँच, गुणवत्ता और सस्ती कीमत - पर ध्यान केंद्रित करके, पीएमबीजेपी ने लाखों लोगों के चिकित्सा खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है। निरंतर संस्थागत समर्थन, लोगों की बढ़ती जागरूकता औरअवसंरचनात्मक सुधारों के साथ, हर जिले में जनऔषधि केंद्र का सपना अब दूर की आकांक्षा नहीं,बल्कि यह ठोस रूप ले चुका है और वास्तविकता के करीब है।

'विकसित भारत @2047' दृष्टि के तहत मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हर किसी के लिए एक सुदृढ़, न्यायसंगत और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई जाए। इसमें बेहतर अस्पताल, कम चिकित्सा खर्च, उपचार तक आसान पहुंचऔर सस्ती दवाओं की उपलब्धता शामिल हैं। बहु-क्षेत्रीय सहयोगों के जरिये, पीएमबीजेपी ने यह साबित किया है कि सही संस्थागत दृष्टि के साथ, स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणवत्ता युक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ दोनों हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह परियोजना प्रगति करती रहे और किफायती स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर बनाए रखे।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)

राज्यसभा चुनाव 2026

10 राज्यों की 37 सीटों पर सियासी मुकाबला, दलों ने उतारे दिग्गज उम्मीदवार

भारत की संसद का उच्च सदन राज्यसभा देश की संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। वर्ष 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस बार 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है और उसी दिन शाम तक परिणाम आने की संभावना है।

राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। यही कारण है कि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की रणनीति और गठबंधन काफी अहम भूमिका निभाते हैं।

महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी राजनीतिक सक्रियता देखने को मिली। शरद पवार के नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। नामांकन के अंतिम दिन महाराष्ट्र में कुल छह उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इस चुनाव को राज्य की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं।

बिहार में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नितिन नवीन और शिवेंद्र कुमार ने उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। बिहार में सत्तारूढ़ दलों और विपक्ष के बीच राजनीतिक समीकरण इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल किया गया है। तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इन उम्मीदवारों पर भरोसा जता रही है।

कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने तेलंगाना से को उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ से को दोबारा मौका दिया गया है, जो पहले से राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और तेलंगाना की दूसरी सीट से को उम्मीदवार बनाया गया है। अनुराग शर्मा को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की पार्टी ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट दी है। इस सीट से कांग्रेस ने को उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला राज्य में गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है।

भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कई चरणों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने अब तक कुल 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा पार्टी ने असम से तेरस गोवाला और जोगेंद्र मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा तथा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है।

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। मतदान के बाद उसी दिन शाम तक मतगणना पूरी होने की संभावना है। इन चुनावों के परिणाम संसद के उच्च सदन में विभिन्न दलों की ताकत को प्रभावित करेंगे।

राज्यसभा चुनाव 2026 भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कई बड़े राजनीतिक दलों ने अपने प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। अब सभी की निगाहें 16 मार्च को होने वाले मतदान और परिणामों पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में राज्यसभा के राजनीतिक संतुलन को तय करेंगे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

इस सम्मान के साथ पचमढ़ी देश का पहला पर्वतीय पर्यटन स्थल बना

सतपुड़ा की रानी का वैश्विक गौरव, पचमढ़ी को मिला हरित गंतव्य कांस्य सम्मान

मध्यप्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और 'सतपुड़ा की रानी' के नाम से प्रसिद्ध पचमढ़ी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व के प्रतिष्ठित पर्यटन आयोजन आईटीबी बर्लिन ट्रैवल मार्ट में पचमढ़ी को हरित गंतव्य कांस्य प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन नीदरलैंड स्थित संस्था ग्रीन डेस्टिनेशन्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। इस सम्मान के साथ पचमढ़ी देश का पहला पर्वतीय पर्यटन स्थल बन गया है, जिसे यह अंतरराष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश पर्यटन मंडल की ओर से उज्जैन के आयुक्त आशीष सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया।

यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि उत्तरदायी और सतत पर्यटन की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश में पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति के साथ जोड़कर विकसित करने की नीति पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तरदायी पर्यटन की अवधारणा को लगातार मजबूत कर रही है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि पचमढ़ी को मिला यह सम्मान दर्शाता है कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को भी समान महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से पचमढ़ी को वैश्विक स्तर पर एक सतत पर्यटन गंतव्य के रूप में नई पहचान मिलेगी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने की संभावनाएं और मजबूत होंगी। मध्यप्रदेश पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक इलैयाराजा टी ने कहा कि यह सम्मान पचमढ़ी में किए जा रहे संरक्षण और प्रबंधन कार्यों की वैश्विक स्वीकृति है। उन्होंने बताया कि यहां धरोहर संरक्षण, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संतुलन, जलवायु संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। यही कारण है कि पचमढ़ी अब देश के अन्य पर्वतीय पर्यटन स्थलों और पर्यावरण आधारित पर्यटन क्षेत्रों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।

हरित गंतव्य प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पर्यटन स्थलों को कई कठोर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। पचमढ़ी का चयन भी एक विस्तृत और सूक्ष्म मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद किया गया। इस प्रक्रिया में गंतव्य प्रबंधन, प्राकृतिक परिदृश्य, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, सामाजिक कल्याण तथा पर्यटन से जुड़े व्यापारिक संचार जैसे छह प्रमुख विषयों के अंतर्गत 75 से अधिक मापदंडों पर परीक्षण किया गया। इस मूल्यांकन में पचमढ़ी ने 10 में से 6.5 अंक प्राप्त किए और लगभग 40 प्रतिशत वैश्विक सतत पर्यटन मानकों के अनुरूपता स्तर को हासिल किया।

इस उपलब्धि के पीछे मध्यप्रदेश पर्यटन मंडल की सुनियोजित पहल और निरंतर प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नवंबर 2025 में पचमढ़ी में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें पर्यटन विशेषज्ञों, स्थानीय हितधारकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इसके बाद व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन, जानकारी संकलन और दस्तावेज तैयार करने का कार्य किया गया। फरवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय परीक्षक द्वारा पचमढ़ी का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके बाद इसे हरित गंतव्य कांस्य प्रमाणन के लिए चयनित किया गया।प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध पचमढ़ी लंबे समय से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। अब हरित गंतव्य कांस्य सम्मान मिलने के बाद यह स्थान सतत पर्यटन के एक सफल उदाहरण के रूप में भी पहचान बना रहा है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यदि पर्यटन विकास को पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो पर्यटन न केवल आर्थिक विकास का माध्यम बन सकता है बल्कि प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण का भी प्रभावी साधन बन सकता है। पचमढ़ी की यह उपलब्धि न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है और आने वाले समय में भारत के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी एक नई दिशा तय करती है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार सक्रिय

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। विशेष रूप से अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने कई देशों की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित किया है। इस तनावपूर्ण परिस्थिति का प्रभाव उन देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर भी पड़ रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, कामगार, व्यापारी और पर्यटक शामिल हैं।

कई देशों में स्थिति अस्थिर होने के कारण भारतीय नागरिकों के फंसने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे समय में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए व्यापक प्रयास शुरू किए हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कई देशों के नेताओं से बातचीत की है। कूटनीतिक स्तर पर लगातार संवाद स्थापित कर भारत सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के बीच लगातार समन्वय बनाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उन देशों के नेतृत्व से संपर्क साधा है, जहां भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं या जहां हाल के हमलों का असर देखा जा रहा है। इन चर्चाओं का उद्देश्य भारतीयों के सुरक्षित आवागमन के लिए मार्ग तैयार करना और आवश्यक सुरक्षा सहयोग प्राप्त करना है।

इस संकट की घड़ी में भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी तरह सक्रिय है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया के विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क बनाए रखें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कई हेल्पलाइन नंबर और आपात संपर्क जारी किए हैं, जिनके माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक या उनके परिवारजन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके लोग अपने परिजनों की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं और आवश्यक

सहायता भी मांग सकते हैं। पश्चिम एशिया के कई देशों में भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई सहित कई स्थानों पर भारतीय नागरिक कामकाज, पढ़ाई और पर्यटन के उद्देश्य से मौजूद हैं। वर्तमान तनावपूर्ण हालात में इन क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों के कारण जिन देशों की स्थिति प्रभावित हुई है, वहां रहने वाले भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशों में फंसे किसी भी भारतीय नागरिक को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विशेष विमान या अन्य सुरक्षित मार्गों के माध्यम से भारतीयों को स्वदेश लाने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे पहले भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला चुकी है। सरकार का प्रयास है कि सबसे पहले छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं और पर्यटकों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही स्थानीय भारतीय समुदाय और स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ली जा रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को भोजन, आवास और चिकित्सा सहायता मिल सके।

विदेश मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने पासपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखें, स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह संकट भले ही गंभीर हो, लेकिन भारत सरकार की त्वरित और संगठित कार्रवाई से विदेशों में रह रहे भारतीयों को भरोसा मिला है कि उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थिति के अनुसार और भी कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने देश लौट सकें।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)